राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग)
8वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

फा0संख्या-11(24)/Admn./LJ&LA/2025/2815-2816-न्यायिक/ दिनांक 22/3/25

सेवा में,

श्रीमान् उपसचिव प्रश्न शाखा,
पुराना सचिवालय दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

विषयः— दिनांक 24.03.2025 को सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 64

महोदय,

उपरोक्त विषयक में आपके पत्र संख्या सं.एफ.11(बी—1)VIII /2025—30/वि.स.स./प्रश्न शा./2062 दिनांक 15.03.2025 जिसमें विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग से प्रश्नों का जवाब मांगा गया, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस मुद्दे पर माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी की पूर्व स्वीकृति ली गई है।

(हस्ताक्षर) 22/3/2025
उपसचिव(प्रशासन)

संलग्नः— उपरोलिखित
प्रतिलिपिः— निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय
पुराना सचिवालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (150 प्रति संलग्न)

(हस्ताक्षर) 22/3/2025
उपसचिव(प्रशासन)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग)
8वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्याः— **64**

दिनांकः— **24.03.2025**

प्रश्नकर्त्ता का नामः— श्री इमरान हुसेन

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

64.क) वर्तमान में कितने नए जिला न्यायालय निर्माणाधीन हैं व इनमें से प्रत्येक में कितने कितने 'कोर्टरूम व वकीलों के चेंबर बनाए जा रहे हैं;	वर्तमान में 03 नए जिला न्यायालय निर्माणाधीन हैं:- 1. कड़कडडूमा न्यायालय परिसरः- 50 न्यायकक्ष 2. शास्त्री पार्क न्यायालय परिसरः- 48 न्यायकक्ष एवं 250 अधिवक्ता कक्ष 3. रोहिणी सेक्टर-26:- 100 न्यायकक्ष एवं 270 अधिवक्ता कक्ष
ख) इन न्यायालयों का शिलान्यास किस तिथि को किया गया था,	लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ''कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर, शास्त्री पार्क न्यायालय परिसर, रोहिणी सेक्टर —26 को शिलान्यास 02.07.2024 को हुआ था''
ग) दिनांक 20.02.2025 के बाद से माननीय लोक निर्माण मंत्री ने इन जिला न्यायालयों के निर्माण स्थलों का दौरा किया है;	लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उस विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
घ) दिनांक 20.02.2025 के बाद से माननीय विधि एवं न्यायमंत्री ने इन जिला न्यायालयों के निर्माण स्थलों का दौरा किया है; और	माननीय मंत्री के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस तरह का कोई दौरा नहीं किया गया है।
ड.) क्या माननीय विधि एवं न्यायमंत्री या लोकनिर्माण विभाग मंत्री ने इन न्यायालयों के निर्माण के संबंध में दिनांक 20.02.2025 के बाद कोई समीक्षा बैठक की है?	जी हाँ।

रितेश सिंह

प्रधान सचिव
(विधि,न्याय एवं विधायी कार्य)